

विहगावलोकन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

2007 की गतिविधियाँ

1.1 वैश्विक अर्थव्यवस्था, विस्तार की बनी हुई अवधि के बाद, वैश्विक वित्तीय संकट¹ के कारण अब गिरावट की ओर प्रवेश कर रही है। वैश्विक जीडीपी 2004-07 की चार वर्ष की अवधि में 5 प्रतिशत वार्षिक की औसत दर से बढ़ी, जो 1970 के दशक के प्रारंभ से सर्वाधिक बनी हुई दर है। 2007 में वैश्विक जीडीपी में 5.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वैश्विक वृद्धि (जिसकी माप क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर की गयी) का लगभग तीन-चौथाई उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं विशेषतः चीन (11.9 प्रतिशत), भारत (9.3 प्रतिशत) तथा रूस (8.1 प्रतिशत) में आयी व्यापक आधार वाली वृद्धि का परिणाम था। अमरीका में 2.0 प्रतिशत, यूरो क्षेत्र में 2.6 प्रतिशत तथा जापान में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शायी।

1.2 मुद्रास्फीति आम तौर पर नियंत्रित रही, यद्यपि ऊपर की ओर कुछ वृद्धि हुई। प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में से यूएस और यूके में हेडलाइन मुद्रास्फीति में अगस्त 2007 तक थोड़ी कमी आयी तथा सितंबर 2007 के आरंभ से उसमें वृद्धि हुई। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, हेडलाइन मुद्रास्फीति दिसंबर 2007 में अमरीका में 4.1 प्रतिशत, यूके में 2.1 प्रतिशत, यूरो क्षेत्र में 3.1 प्रतिशत तथा जापान में 0.7 प्रतिशत थी, जबकि दिसंबर 2006 में यह क्रमशः 2.5 प्रतिशत, 3.0 प्रतिशत, 1.9 प्रतिशत तथा 0.3 प्रतिशत थी। तथापि अनाज, धातु और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि के साथ घरेलू मांग में हुई वृद्धि के कारण उभरते एशिया के कई देशों में मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ा।

1.3 अगस्त 2007 से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल थी, जो अमरीका के सब-प्राइम बंधक बाजार द्वारा प्रेरित थी, जो बाद के महीनों में फैल गयी। वित्तीय संस्थाओं ने विश्वभर में हानियाँ दर्ज कीं, जिसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर राशि बट्टे खाते डाली गयी तथा कुछ बड़े अंतरराष्ट्रीय बैंकों के लाभ में काफी गिरावट आयी।

1.4 जून 2007 से प्रारंभ हुई अवधि के दौरान अमरीकी सब-प्राइम बंधक ऋणों में हुई हानियों की चिंता ने बढ़कर व्यापक वित्तीय तनाव का रूप धारण कर लिया, जिससे बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं की स्थिरता के बारे में आशंका उत्पन्न हो गयी। अवधि के दौरान वैश्विक ऋण बाजारों में बड़े पैमाने पर बिक्री की गयी क्योंकि व्यापक आधार वाली डीलिवरेजिंग के साथ ऋण संबंधी एक्सपोजर की मात्रा और उसके मूल्यन के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न हो गयी। इस प्रक्रिया में समस्त बाजारों में 2007 के प्रारंभ में देखे गये अस्वाभाविक रूप से सख्त स्तरों की तुलना में क्रेडिट स्प्रेड में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई। बढ़ते हुए स्प्रेड के साथ ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) सूचकांक विकल्पों द्वारा अभिप्रेत अस्थिरता में काफी वृद्धि हुई। अशांति के दौरान प्रारंभ में आयी थोड़ी रुकावट के बाद 2002-03 के सूचकांक के प्रारंभ से देखे गए स्तरों की तुलना में अस्थिरता अधिक बनी हुई है, जो अल्पावधि गतिविधियों के बारे में अत्यधिक अनिश्चितता को सूचित करता है। बदले में, निवेशकों के जोखिम सहने की शक्ति में गिरावट आने के फलस्वरूप ऋण उत्पादों के लिए जोखिम प्रीमियम तेजी से बढ़ गया। ऋण जोखिम का मूल्य, जिसे कम गुणवत्ता वाले उधारकर्ताओं की अभिप्रेत एवं अनुभूत चूक संबंधी संभाव्यताओं के क्रेडिट स्प्रेड से ज्ञात किया गया, जून तथा जुलाई 2008 में उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया तथा 2008 के उत्तरार्ध में उसमें और वृद्धि हो गयी। जैसे-जैसे आस्तित्व समर्थित वाणिज्यिक पत्र (एबीसीपी) में गतिविधियाँ

¹ इस अध्याय में वैश्विक गतिविधियाँ कैलेंडर वर्ष (जनवरी से दिसंबर) से संबंधित हैं, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिविधियाँ, अन्यथा विनिर्दिष्ट न होने पर, राजकोषीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) से संबंधित हैं।

कम होती गयीं, बैंकों द्वारा उनके तुलन पत्रों में एबीसीपी एक्सपोजर लेने के लिए बाध्य किए जाने संबंधी चिंताओं के कारण आनेवाले ऋण संकट के बारे में आशंकाएं पैदा हो गयीं। वाणिज्यिक पत्र जारी करनेवाली संस्थाओं की दीर्घ अवधि के वित्तपोषण में असमर्थता ने उनके प्रायोजक बैंकों से चलनिधि की मांग करने के लिए प्रेरित किया जिससे, बदले में, बैंक चलनिधि इकट्ठा करने के लिए प्रेरित हुए। प्रतिपक्ष की आस्तियों की गुणवत्ता की बारे में आयी अनिश्चितता ने भी स्थिति को गंभीर बना दिया। इस प्रकार खलबली अल्पावधि मुद्रा बाजारों में फैल गयी जिसके कारण अगस्त 2007 में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एक दिवसीय ब्याज दरों में तीव्र वृद्धि हुई क्योंकि तुलनपत्र बाह्य साधनों से आस्तियों, जिसके लिए वे निधीयन प्राप्त करने में समर्थ नहीं थे तथा सब-प्राइम प्रतिभूतियां और अन्य विन्यस्त ऋण रखने पर बैंकों की हानियों के आकार और उसके वितरण, को अवशोषित करने के दबावों को देखते हुए बैंकों ने अपनी चलनिधि को संरक्षित रखने की मांग की।

1.5 ब्रिटेन ने अंतर-बैंक दरों में कुछ तीव्रतम वृद्धि देखी क्योंकि बंधक ऋणदाता नार्दन रॉक में चलनिधि की अपेक्षाएं अधिक बढ़ गयीं जिससे अंततः बैंक में भगदड़ मच गयी। औद्योगिक देशों में सरकारी बांड के प्रतिफल में तीव्र गिरावट आयी, जो जोखिम से बचने तथा फलस्वरूप सुरक्षा की ओर निवेशकों के पलायन को दर्शाता है। अमरीका के दस साल के बांड का प्रतिफल 13 जून 2007 के 5.19 प्रतिशत से गिरकर 23 जनवरी 2008 को 3.42 प्रतिशत रह गया। यूरो क्षेत्र में दस वर्षीय बांड का प्रतिफल 9 जुलाई 2007 के 4.63 प्रतिशत से गिरकर 23 जनवरी 2008 को 3.88 प्रतिशत रह गया। जापान के दस वर्षीय बांड का प्रतिफल 13 जून 2007 के 1.94 प्रतिशत से गिरकर 23 जनवरी 2008 को 1.34 प्रतिशत रह गया। उन्नत औद्योगिक अर्थव्यवस्था में ऋण बाजार संबंधी उथल-पुथल शुरू होने के दौरान सीडीएस-स्प्रेड बढ़ने के फलस्वरूप 2007 के ग्रीष्मकाल में इक्विटी की कीमतों में गिरावट आनी शुरू हो गयी। अमरीका के समस्त आर्थिक दृष्टिकोण की बदतर होती स्थिति ने भविष्य के लाभ और निवेशकों की जोखिम सहने की सीमा में कमी आने के बारे में चिंताओं को प्रेरित किया। 2007 की पहली छमाही में, उभरते बाजार की आस्तियों की कीमतों में उछाल आयी, जिसे सुदृढ़ आर्थिक

कार्यनिष्पादन तथा उनके इक्विटी बाजारों में सुदृढ़ संविभाग पूंजी प्रवाहों के एक और वर्ष से समर्थन मिला। तथापि, वर्ष की दूसरी छमाही में जोखिम के सामान्य पुनर्मूल्यन के अनुरूप उभरते बाजार के आस्ति मूल्य में काफी उतार-चढ़ाव देखे गए, यद्यपि ये उतार-चढ़ाव कुछ परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं में उस समय देखे गए उतार-चढ़ाव जितने बड़े नहीं थे।

1.6 अन्य वित्तीय बाजारों में उल्लेखनीय अव्यवस्था के फलस्वरूप अगस्त 2007 में विदेशी मुद्रा बाजारों में अस्थिरता काफी बढ़ गयी। यह बाजार गतिविधियों को चालित करनेवाले कारकों में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। जून 2007 के बाद, अमरीकी डॉलर में बना हुआ मूल्यहास तेज हो गया। 2006 तथा 2007 की पहली छमाही के दौरान, यूरो की तुलना में अमरीकी डॉलर में 9 प्रतिशत की वार्षिकीकृत दर से मूल्यहास हुआ तथा येन की तुलना में उसमें सीमांत वृद्धि हुई। जुलाई 2007 की शुरुआत तथा अप्रैल 2008 के अंत के बीच, मूल्यहास की वार्षिकीकृत दर बढ़कर दोनों मुद्राओं की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत हो गयी। इसी तरह, जुलाई 2007 तथा अप्रैल 2008 के बीच स्टर्लिंग में प्रभावी तौर पर लगभग 15 प्रतिशत का मूल्यहास हुआ। इस अवधि में रूसी रूबल जैसी अन्य मुद्राओं में सांकेतिक प्रभावी तौर पर निरंतर मूल्यहास हुआ। इसके विपरीत, 2007 की दूसरी छमाही और 2008 में कई मुद्राओं में प्रभावी तौर पर मूल्यवृद्धि हुई।

2008 की गतिविधियां

1.7 2008 में वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल में अब तक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा वास्तविक क्षेत्र में इसका प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। कई उन्नत अर्थव्यवस्थाएं मंदी की स्थिति से गुजर रही हैं। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि भी कमजोर पड़ रही है। वित्तीय संकट सितंबर 2008 से उथल-पुथल के नए चरण में पहुंच गया है जिसने वैश्विक वित्तीय संस्थाओं और बाजारों में विश्वास को अत्यधिक प्रभावित किया है। नवंबर 2008 में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आइएमएफ) द्वारा विश्व आर्थिक दृष्टिकोण

के बारे में जारी अद्यतन स्थिति के अनुसार, वैश्विक वृद्धि की संभावनाएं कम हो गई हैं क्योंकि वित्तीय क्षेत्र की डीलिवरेजिंग जारी है तथा उत्पादक एवं उपभोक्ता के विश्वास में गिरावट आई है। तदनुसार, विश्व का उत्पादन गिरकर 2008 में 3.7 प्रतिशत तथा और गिरकर 2009 में 2.2 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है।

1.8 2008 की दूसरी तिमाही में उन्नत तथा उभरती बाजार वाली दोनों अर्थव्यवस्थाओं में मंदी देखी गयी है। सभी प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं यथा यूरो क्षेत्र, जापान, कोरिया, यूके, अमरीका तथा ओईसीडी देशों ने 2008 की पहली तिमाही की तुलना में 2008 की दूसरी तिमाही में कम वृद्धि दर्ज की। उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं यथा अर्जेंटीना, चीन, भारत, मलेशिया तथा थाईलैंड में भी 2008 की दूसरी तिमाही में वृद्धि में गिरावट देखी गयी।

1.9 अगस्त 2008 तक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़ी, जो अनाज और ईंधन की कीमतों में वृद्धि तथा विशेष तौर पर उभरते बाजारों में मांग की सुदृढ़ स्थितियों के संयुक्त प्रभाव को दर्शाता है। बाद में, अनाज तथा ईंधन की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट तथा वैश्विक वित्तीय बाजार संकट तीव्र होने के कारण वृद्धि में अधोमुखी जोखिम बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति में नरमी आई। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, अमरीका में हेडलाइन मुद्रास्फीति अक्टूबर 2008 में गिरकर 3.7 प्रतिशत होने के पहले जुलाई 2008 में बढ़कर 5.6 प्रतिशत (एक साल पहले के 2.4 प्रतिशत से) हो गई। यूके में सीपीआई मुद्रास्फीति बढ़कर सितंबर 2008 में 5.2 प्रतिशत (1.8 प्रतिशत से) हो गई, परंतु अक्टूबर 2008 तक गिरकर 4.5 प्रतिशत रह गई तथा यूरो क्षेत्र में नवंबर 2008 तक तेजी से गिरकर 2.1 प्रतिशत होने के पूर्व जुलाई 2008 में 4.0 प्रतिशत (1.8 प्रतिशत से) हो गई। सुदृढ़ वृद्धि, पण्य मूल्यों में वृद्धि तथा अगस्त 2008 तक पर्याप्त चलनिधि के समर्थन से अधिकांश उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति में तेजी आई तथा उसके बाद वह कम हो गई। तथापि, वैश्विक स्तर पर हाल के महीनों में कई देशों में मुद्रास्फीति में नरमी आई है। आइएमएफ के अनुसार पण्य की स्थिर हो रही कीमतों तथा अर्थव्यवस्था में मंदी का मिश्रण मुद्रास्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करने में मदद करेगा।

1.10 वित्तीय बाजारों में तनाव काफी बढ़ गए क्योंकि ऋणात्मक चक्रीय प्रत्याशाओं को आवास बाजार में आयी और रुग्णता के कारण बल मिल गया। अमरीका में भविष्य में मकान की कीमतों के मूल्यहास का अनुमान बढ़ने के साथ बंधक संबंधी चूक एवं मोचन-निषेध में और वृद्धि हो गयी। रुख में और गिरावट आयी क्योंकि 'फैन्नी मे' तथा 'फ्रेड्डी मैक' नामक अमरीकी सरकार द्वारा प्रवर्तित दो बंधक प्रतिभूतिकरण कंपनियों की हानियों और दीर्घावधि संभावना के बारे में चिंताएं बढ़ गयीं।

1.11 जहां बाजार में कमजोरी बनी रही, वहीं आस्ति वर्गों के मूल्यन के आधार पर आर्थिक दृष्टिकोण तथा संबंधित अनिश्चितताओं के बारे में चिंताएं बढ़ गयीं। मई 2008 के अंत से ऋण बाजारों में नए सिरे से दबाव देखे गए क्योंकि बढ़े हुए स्प्रेड में हानि की प्रत्याशाओं और वित्तीय क्षेत्र के तुलनपत्रों के लिए चल रहे चक्रीय समायोजन के निहितार्थ झलक रहे थे। कंपनियों की आय तथा ऋण की गुणवत्ता में कमी आयी क्योंकि निविष्टि की लागत बढ़ गयी तथा उच्चतर मुद्रास्फीति और न्यूनतर वृद्धि के माहौल में मांग कम हो गयी। प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बांड के प्रतिफल में गिरावट आयी जो सुरक्षितता की ओर जाने, वृद्धि की संभावना के खराब होने परंतु संभवतः मुद्रास्फीति के अल्पावधि दृष्टिकोण में सुधार को दर्शाता है। वृद्धि के बारे में चिंता, अग्रणी निवेश बैंकों द्वारा और वित्तीय हानि के समाचार और आय में गिरावट के कारण इक्विटी बाजार में गिरावट आयी। अंतरबैंक मुद्रा बाजार में निधीयन संबंधी दबाव बना रहा तथा वित्तीय क्षेत्र अवलेखन, कमजोर इक्विटी बाजार, प्रतिपक्ष ऋण जोखिम और चलनिधि कारकों के बारे में नवीकृत चिंताओं के कारण लंदन अंतरबैंक प्रस्ताव दर (लिबोर) और तदनुरूप एकदिवसीय सूचकांकित स्वैप (ओआइएस) दरों के बीच स्प्रेड बढ़ गया। अगस्त 2008 के उत्तरार्ध तक सीडीएस स्प्रेड बढ़ गया क्योंकि अमरीका का पंचवर्षीय सीडीएस उच्च प्रतिलाभ सूचकांक स्प्रेड लगभग 136 आधार अंक बढ़कर 700 आधार अंक के ऊपर पहुंच गया। यूरो तथा जापान के सीडीएस सूचकांकों ने मोटे तौर पर अपने अमरीकी प्रतिपक्षियों के कार्यनिष्पादन की नकल की।

1.12 2008 की तीसरी तिमाही के दौरान उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अल्पावधि ब्याज दरों में मिश्रित प्रवृत्ति रही तथा वह मोटे तौर पर नीतिगत दरों के आसपास रही। अमरीका में अल्पावधि ब्याज दरों में गिरावट आयी। अमरीकी फेड ने जून, अगस्त और सितंबर 2008 में हुई अपनी बैठकों में 2.0 प्रतिशत पर फेड फंड दर का लक्ष्य अपरिवर्तित रखा। 18 सितंबर 2007 और 30 अप्रैल 2008 के बीच फेड फंड दर के लक्ष्य में बार बार की गयी कटौतियों के बाद यह रुकावट आयी। 2007-08 की दूसरी छमाही तथा अप्रैल 2008 में नीति दर में कटौती के बावजूद यूके में अल्पावधि ब्याज दरें बढ़ गईं। बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिसने अपनी नीति दर मई 2007 और जुलाई 2007 में बढ़ा दी थी, मंद वृद्धि की चिंताओं के कारण दिसंबर 2007, फरवरी 2008 और अप्रैल 2008 में दर में कटौती करके उसे 5.0 प्रतिशत कर दिया। सितंबर 2008 को समाप्त तिमाही में यूरो क्षेत्र में अल्पावधि ब्याज दरें बढ़ गयीं। 3 जुलाई 2008 को यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अपनी पुनर्वित्त दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि की। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से अर्जेंटीना, चीन तथा फिलीपीन्स में अल्पावधि ब्याज दरें आम तौर पर नरम रहीं परंतु ब्राजील, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड में उनमें तेजी आयी। सितंबर 2008 में पीपल्स बैंक ऑफ चायना ने अपने बेंचमार्क उधार दर में 0.27 प्रतिशत अंकों की कटौती की तथा आरक्षित निधि के अपेक्षित अनुपात में भी 1 प्रतिशत अंक की कटौती की। 6 प्रमुख केंद्रीय बैंकों अर्थात् फेडरल रिज़र्व, दि यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ईसीबी), दि बैंक ऑफ इंग्लैंड, दि रिक्स बैंक, दि स्विस् नेशनल बैंक तथा दि बैंक ऑफ कनाडा द्वारा समन्वित रूप से 7 अक्टूबर 2008 को दर में की गयी आधे अंकों की कटौती वैश्विक इक्विटी तथा अंतरबैंक बाजारों में आयी घबराहट को शांत करने के लिए किया गया एक अभूतपूर्व प्रयास है। फेडरल रिज़र्व ने 29 अक्टूबर 2008 को नीति दर में 50 आधार अंकों की और कटौती कर उसे 1.0 प्रतिशत कर दिया, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 6 नवंबर 2008 को 150 आधार अंकों की कटौती कर 3.0 प्रतिशत तथा रिक्सबैंक ने 29 अक्टूबर 2008 को 50 आधार अंकों की कटौती कर 3.75 प्रतिशत कर दिया।

1.13 प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में दीर्घावधि सरकारी बांड प्रतिफल, जिसमें मार्च 2008 के अंत में नरमी आ गयी थी, 2008 की दूसरी तिमाही में बढ़ गया तथा 2008 की तीसरी तिमाही में उसमें पुनः नरमी आ गयी जो वृद्धि की प्रत्याशाओं के खराब होने और मुद्रास्फीति की अल्पकालिक संभावना में सुधार को दर्शाता है।

1.14 इक्विटी बाजार, जिसमें अप्रैल-मई 2008 के दौरान कुछ सुधार हुआ था, उसके बाद अत्यधिक अस्थिर हो गया। 2008 की तीसरी तिमाही में, अधिकांश विकसित और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के इक्विटी बाजारों में वित्तीय संस्थाओं की स्थिति, तेल की कीमतों में वृद्धि, अमरीका, यूरोप और एशिया में आर्थिक मंदी पर चिंता, ऋण हानियां बढ़ने, उच्च मुद्रास्फीति और कंपनियों की आय में गिरावट की आशंका संबंधी नकारात्मक खबरों के कारण गिरावट आयी।

1.15 विदेशी मुद्रा बाजार में अप्रैल-जुलाई 2008 में अमरीकी डॉलर का मूल्यहास हुआ था, परंतु बेरोजगारी की दर में वृद्धि एवं मकान की बिक्री में बनी हुई कमी के बावजूद अगस्त 2008 के आरंभ से उसमें मूल्यवृद्धि हुई। तथापि, अगस्त 2008 के आरंभ से अमरीकी डॉलर की सुदृढ़ता अमरीका और यूरोप के बीच वृद्धि संबंधी अंतर कम होने, अमरीकी निवेशकों द्वारा विदेशी इक्विटी एवं बांड बाजारों में स्थिति के समापन और यूरो क्षेत्र में वृद्धि में आयी कमी के कारण अमरीका को धन वापस भेजने को दर्शाता है। मार्च 2008 तथा नवंबर 2008 के बीच अमरीकी डॉलर के मूल्य में यूरो की तुलना में 24.2 प्रतिशत, पौंड स्टर्लिंग की तुलना में 29.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई परंतु येन की तुलना में 4.8 प्रतिशत का हास हुआ। एशियाई मुद्राओं में अमरीकी डॉलर चीनी युआन की तुलना में 2.7 प्रतिशत घटा परंतु उसमें कोरियाई वोन की तुलना में 52.2 प्रतिशत, भारतीय रुपये की तुलना में 24.7 प्रतिशत, रूसी रूबल की तुलना में 16.4 प्रतिशत, मलेशियाई रिंगिट की तुलना में 13.6 प्रतिशत तथा थाई बाॅथ की तुलना में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

भारतीय अर्थव्यवस्था

समष्टि वातावरण

1.16 2007-08 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज वृद्धि बनी रही, हालांकि उसमें कुछ कमी आयी। 2007-08 में वास्तविक सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 9.0 प्रतिशत थी जो 2006-07 के 9.6 प्रतिशत से कम थी और यह उद्योग एवं सेवा में आयी कुछ कमी को दर्शाती है। वर्ष के दौरान एक सकारात्मक विशेषता यह थी कि पिछले साल अनुभव की गयी मंदी के बाद कृषि क्षेत्र में वास्तविक जीडीपी की वृद्धि में सुधार हुआ। इस कमी के बावजूद, 2007-08 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि दर वैश्विक संदर्भ में उल्लेखनीय थी।

1.17 2007-08 में, औद्योगिक क्षेत्र से उत्पन्न वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2006-07 के 10.6 प्रतिशत की तुलना में कम होकर 8.2 प्रतिशत रह गई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) के रूप में, औद्योगिक वृद्धि 2006-07 के 11.5 प्रतिशत की तुलना में 8.5 प्रतिशत थी। 2007-08 में विनिर्माण क्षेत्र में हुई 9.0 प्रतिशत की वृद्धि (2006-07 में 12.5 प्रतिशत) पिछले चार वर्षों में सबसे कम थी। खनन और बिजली क्षेत्रों में भी 2007-08 में मंद गति से वृद्धि हुई। उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, 18.0 प्रतिशत वृद्धि के साथ पूंजीगत माल क्षेत्र का कार्यनिष्पादन विशेष तौर पर प्रभावी था। तथापि, मूलभूत माल, मध्यवर्ती माल तथा उपभोक्ता माल क्षेत्रों में 2007-08 में क्रमशः 7.0 प्रतिशत, 8.9 प्रतिशत तथा 6.1 प्रतिशत की कम वृद्धि दर्ज की गयी। औद्योगिक क्षेत्र का कार्यनिष्पादन भी मूलभूत संरचना क्षेत्र के मंद कार्यनिष्पादन से प्रभावित हुआ तथा 2007-08 में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। सेवा क्षेत्र ने पिछले तीन वर्षों में लगातार दुहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की। इसमें 2006-07 में हुई 11.2 प्रतिशत की वृद्धि के ऊपर 2007-08 में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.18 थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) की गतिविधि के आधार पर भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति एक वर्ष पहले के 5.9 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2008 के अंत में 7.7 प्रतिशत हो गयी।

आरंभ में अक्टूबर 2007 के मध्य तक मुद्रास्फीति में नरमी आयी, जो अंशतः कुछ प्राथमिक खाद्य वस्तुओं और कुछ विनिर्मित उत्पादों के मूल्यों में कमी को दर्शाता है और आधारभूत प्रभाव भी इसका एक कारण है। तथापि, बाद में मुद्रास्फीति बढ़कर 15 मार्च 2008 को 8.0 प्रतिशत की अंतर्वर्ष ऊंचाई पर पहुंच गयी, जो प्रमुख पण्यों पर आपूर्ति पक्ष के दबाव तथा ईंधन की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि को दर्शाता है। 2007-08 में हेडलाइन डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति मुख्यतः 12 मदों/समूहों अर्थात् चावल, गेहूं, दूध, कच्ची रूई, तिलहन, लौह अयस्क, कोयला खनन, खनिज तेल, खाद्य तेल, खली, मूलभूत भारी अकार्बनिक रसायन तथा धातु द्वारा चालित थी और डब्ल्यूपीआइ बास्केट में उसका संयुक्त भार लगभग 35 प्रतिशत था जो 29 मार्च 2008 को साल-दर-साल आधार पर डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति के लगभग 82 प्रतिशत (एक वर्ष पहले के 56 प्रतिशत की तुलना में) के लिए जिम्मेदार था। प्रमुख समूहों में प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन समूह और विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति क्रमशः 9.7 प्रतिशत, 6.8 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत थी।

1.19 2007-08 के बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान में केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतकों के कम होने का अनुमान था। केंद्र सरकार का राजस्व घाटा 63,488 करोड़ रुपए अथवा जीडीपी का 1.4 प्रतिशत अनुमानित किया गया, जो 2007-08 और 2006-07 के बजट अनुमानों में जीडीपी के 1.5 प्रतिशत की तुलना में न्यूनतर था। 2,47,831 करोड़ रुपए पर 2007-08 का संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) पिछले वर्ष के 5.6 प्रतिशत की तुलना में जीडीपी का 5.3 प्रतिशत था। प्राथमिक शेष में अधिशेष की स्थिति बनी रही। प्रमुख राजकोषीय संकेतकों में सुधार को कर राजस्व में उछाल, विशेष तौर पर प्रत्यक्ष कर राजस्व में उछाल द्वारा सुकर बनाया गया था। मार्च 2008 के अंत में 77.0 प्रतिशत पर जीडीपी के अनुपात के रूप में संयुक्त बकाया देयताएं (संशोधित अनुमान) मार्च 2007 के अंत की स्थिति जैसी थीं। केंद्र सरकार की बकाया देयताओं में वृद्धि को राज्य सरकारों की देयताओं में कमी द्वारा प्रतितुलित कर दिया गया।

1.20 31 मार्च 2008 को 20.8 प्रतिशत पर स्थूल मुद्रा (एम₃) में वृद्धि अप्रैल 2007 में वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य में निर्धारित 2007-08 के लिए 17.0 - 17.5 प्रतिशत के सांकेतिक क्षेत्र से ऊपर थी। तथापि, एम3 की वृद्धि दर फरवरी 2008 के मध्य से कम हुई जो आवधिक जमाराशियों की वृद्धि में कुछ कमी को दर्शाता है। 2007-08 में खाद्येतर ऋण की वृद्धि में कमी आयी तथा वह रिजर्व बैंक की नीति में दर्शाए गए 24.0-25.0 प्रतिशत के अनुमान (अप्रैल 2007) की तुलना में थोड़ी कम थी। एसएलआर प्रतिभूतियों में बैंकों का निवेश जमाराशियों में वृद्धि के अनुरूप बढ़ा। फलस्वरूप, एनडीटीएल के अनुपात के रूप में उनका एसएलआर निवेश लगभग मार्च 2007 के अंत के स्तर पर रहा। 2007-08 में 20.6 प्रतिशत पर वाणिज्यिक ऋण की मांग 2006-07 के 25.8 प्रतिशत की तुलना में कुछ कमी को दर्शाता है। वर्ष के दौरान सरकार को वाणिज्यिक बैंकों के ऋण में वृद्धि हुई, जबकि सरकार को रिजर्व बैंक के निवल ऋण में एमएसएस जारी करने के फलस्वरूप गिरावट आयी। बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में 41.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में वृद्धि मौद्रिक विस्तार का प्रमुख स्रोत बनी रही, जबकि वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण की वृद्धि में कमी आयी।

1.21 अगस्त 2007 की दूसरी छमाही, दिसंबर 2007 की दूसरी छमाही के दौरान तथा जनवरी 2008 के दूसरे सप्ताह के शुरू में मांग मुद्रा बाजार में अस्थिरता के संक्षिप्त दौर एवं इक्विटी बाजार में अस्थिरता के आकस्मिक दौर को छोड़कर 2007-08 में देशी वित्तीय बाजारों की स्थिति व्यवस्थित बनी रही, जो मोटे तौर पर अंतरराष्ट्रीय इक्विटी बाजार की प्रवृत्तियों के अनुरूप था। पूंजी बाजार का प्राथमिक बाजार खंड, जिसमें जनवरी 2008 के प्रारंभ तक अधिक क्रियाशीलता देखी गई, द्वितीयक बाजार की अस्थिरता के कारण बाद में मंद पड़ गया। वर्ष के अधिकांश हिस्से में सरकारी प्रतिभूति बाजार के प्रतिफल में नरमी रही।

1.22 रिजर्व बैंक के पास केंद्र सरकार के नकदी शेष तथा पूंजी प्रवाहों में बदलाव के कारण मुद्रा बाजार में अस्थिरता के संक्षिप्त दौर देखे गए। 5 मार्च 2007 से 5 अगस्त 2007 तक चलनिधि समायोजन

सुविधा (एलएएफ) के तहत रिवर्स रिपो स्वीकृतियों पर 3,000 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा लगाने से भी मुद्रा बाजार प्रभावित हुआ। जून-जुलाई 2007 के दौरान मांग/सूचना दरें नरम होकर रिवर्स रिपो दर के नीचे आ गईं। बाद में अगस्त 2007 में एलएएफ के तहत रिवर्स रिपो स्वीकृतियों पर 3,000 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा हटाने के बाद वर्ष के अधिकांश भाग में एक दिवसीय मुद्रा बाजार में ब्याज दरें मोटे तौर पर रिवर्स रिपो तथा रिपो कारिडोर के बीच चलती रहीं। 2007-08 में संपार्श्विकीकृत उधार लेने और उधार देने के दायित्व (सीबीएलओ), बाजार रिपो और मांग/सूचना मुद्रा बाजार में ब्याज दरों का औसत क्रमशः 5.20 प्रतिशत, 5.50 प्रतिशत तथा 6.07 प्रतिशत (एक साल पहले क्रमशः 6.24 प्रतिशत, 6.34 प्रतिशत तथा 7.22 प्रतिशत) था। तीनों मुद्रा बाजार खंडों के लिए भारित औसत दर मिलाकर एक वर्ष पहले के 6.57 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में 5.48 प्रतिशत था, जिसका आंशिक कारण था - मार्च से अगस्त तक की अवधि में, जब एलएएफ अवशोषण पर 3,000 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा थी, एक दिवसीय ब्याज दरों का कम होना।

1.23 2008-09 के दौरान अब तक भारतीय वित्तीय बाजार आम तौर पर व्यवस्थित रहे हैं। 2008-09 की पहली तिमाही की शुरुआत में मुद्रा बाजार दरों में कमी आई, परंतु 2008-09 की दूसरी तिमाही के दौरान वह अधिकांशतः रिपो दर के ऊपर/आसपास बनी रही जो अन्य बातों के साथ-साथ आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) तथा रिपो दर में वृद्धि और रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा बाजार परिचालनों को दर्शाता है। सितंबर 2008 में देशी मुद्रा बाजारों में चलनिधि की सख्त स्थितियों को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने 16 सितंबर 2008 से अनेक उपायों की घोषणा की (ब्यौरे अध्याय II में दिए गए हैं)। फलस्वरूप, औसत मांग दर, जो 10.52 प्रतिशत थी, नवंबर 2008 में गिरकर 7.57 प्रतिशत रह गई।

1.24 2007-08 के दौरान रिजर्व बैंक को न सिर्फ केंद्र सरकार की नकद शेषराशियों में दोलन के कारण अपितु बड़े और अस्थिर पूंजी प्रवाहों के कारण भी चलनिधि में बड़े पैमाने पर घटबढ़ से संतुष्ट

रहना पड़ा। मूल्य और वित्तीय स्थिरता के उद्देश्यों के अनुरूप चलनिधि की स्थितियों में इस प्रकार के दोलन के प्रबंधन के लिए रिजर्व बैंक ने सीआरआर, एलएएफ और एमएसएस का विवेकपूर्ण उपयोग किया। कुल मिलाकर, 2007-08 में 171 दिनों तक चलनिधि का निवल अवशोषण तथा 75 दिनों तक चलनिधि का निवल अंतर्वेशन किया गया। एलएएफ के तहत औसत दैनिक निवल बकाया शेष दिसंबर 2007 के दौरान 10,804 करोड़ रुपए के अंतर्वेशन तथा अक्टूबर 2007 में 36,665 करोड़ रुपए के अवशोषण के बीच घटता-बढ़ता रहा। 2007-08 के दौरान बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के तहत निवल निर्गम 1,05,691 करोड़ रुपए था।

1.25 वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) पर भारत औसत बढ़ा दर (डब्ल्यूएडीआर) 31 मार्च 2007 के 11.33 प्रतिशत से घटकर अक्टूबर 2007 के अंत में 7.65 प्रतिशत हो गई परंतु उसके बाद बढ़कर वह 31 मार्च 2008 को 10.38 प्रतिशत पर पहुंच गई। जमा प्रमाणपत्रों पर डब्ल्यूएडीआर, जो मार्च 2007 के अंत के 10.75 प्रतिशत से घटकर अगस्त 2007 के आरंभ में 7.40 प्रतिशत हो गया था, उसके बाद बढ़कर मार्च 2008 के अंत में 10.00 प्रतिशत हो गया। 2007-08 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) की जमा तथा उधार दरों में वृद्धि हुई।

1.26 2007-08 की पहली तिमाही में जून 2007 के मध्य तक सरकारी प्रतिभूति बाजार पर प्रतिफल कुछ बढ़ गया परंतु उसके बाद उसमें गिरावट आयी। 2007-08 के दौरान, 10 वर्षीय प्रतिफल 7.42-8.32 प्रतिशत के दायरे में चलता रहा। 31 मार्च 2008 को 10 वर्षीय प्रतिफल 7.93 प्रतिशत था, जो मार्च 2007 के अंत की तुलना में चार आधार अंक कम था।

1.27 2007-08 के दौरान, देशी शेयर बाजार 8 जनवरी 2008 तक बढ़ता रहा। 8 जनवरी 2008 तक हुई बढ़त की प्रवृत्ति के बीच-बीच में अगस्त 2007 के मध्य, अक्टूबर 2007 के मध्य तथा दिसंबर 2007 के मध्य में थोड़ा करेक्शन आया। तथापि, 9 जनवरी 2008 से देशी शेयर बाजार अस्थिर हो गया। मार्च 2008 के अंत में बीएसई सेसेक्स 15,644 पर था, जो 8 जनवरी 2008 के 20,873 के सर्वाधिक

उच्च स्तर से 25.1 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। तथापि, यह मार्च 2007 के अंत के स्तर (13,072) की तुलना में अभी भी 19.7 प्रतिशत अधिक था।

1.28 विदेशी मुद्रा बाजार में, 2007-08 के दौरान 39.26 - 43.15 रुपए प्रति अमरीकी डालर के दायरे में भारतीय रुपए में दुतरफा घटबढ़ दिखाई दिया। भारतीय रुपया 31 जुलाई 2007 के 40.43 रुपया प्रति अमरीकी डालर से घटकर 17 अगस्त 2007 को 41.58 रुपया प्रति अमरीकी डालर हो गया। उसके बाद जनवरी 2008 तक रुपए की विनिमय दर में मूल्यवृद्धि हुई। अक्टूबर 2007-जनवरी 2008 के दौरान रुपया 39.26 - 39.84 रु. प्रति अमरीकी डालर के दायरे में चलता रहा। तथापि, एफआईआई के बहिर्वाह, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों तथा तेल कंपनियों द्वारा डालर की भारी मांग के कारण फरवरी 2008 के आरंभ से अमरीकी डालर की तुलना में रुपए में मूल्यहास आरंभ हो गया। मार्च 2008 के अंत में रुपए की विनिमय दर 39.99 रु. प्रति अमरीकी डालर थी।

1.29 वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआइएण्डएस) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के पण्य निर्यात में 2006-07 के 22.6 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में 28.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। भारत के आयात की वृद्धि 2006-07 के 24.5 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 35.4 प्रतिशत हो गई। भुगतान संतुलन आधार पर भारत का पण्य व्यापार घाटा 2006-07 के 63.2 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2007-08 में 90.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। 2007-08 के दौरान अदृश्य अधिशेष में निरंतर वृद्धि से पण्य व्यापार के बढ़ते घाटे के प्रभाव को कम किया जाना जारी रहा। फलस्वरूप, 2007-08 के दौरान चालू खाता घाटा 17.4 बिलियन अमरीकी डालर (2006-07 में 9.8 बिलियन अमरीकी डालर) हो गया। जीडीपी के अनुपात के रूप में 2007-08 में 1.5 प्रतिशत पर चालू खाता घाटा उच्चतर व्यापार घाटे की अगुवाई में पिछले साल (1.1 प्रतिशत) की तुलना में उच्चतर था। निवल पूंजी प्रवाह चालू खाता घाटा से अधिक बने रहने के कारण समग्र भुगतान संतुलन में उल्लेखनीय अधिशेष दर्ज

किया गया जो मार्च 2007 के अंत के 199.2 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि बढ़कर मार्च 2008 के अंत में 309.7 बिलियन अमरीकी डालर हो जाने में दिखाई दिया। उच्चतर बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) तथा अल्पावधि ऋण को दर्शाते हुए बाह्य ऋण मार्च 2008 के अंत तक बढ़कर 221.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

अनुसूचित वाणिज्य बैंक

1.30 बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों में वास्तविक अर्थव्यवस्था की तुलना में तीव्रतर दर से वृद्धि होनी जारी रही, जिसके फलस्वरूप एक वर्ष पहले के 83.5 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2008 के अंत में जीडीपी के प्रति आस्तियों का अनुपात बढ़कर 91.8 प्रतिशत हो गया। वर्ष के दौरान मुख्यतः कृषि तथा संबंधित कार्यकलाप एवं वैयक्तिक ऋणों में निम्नतर वृद्धि के कारण ऋण की वृद्धि में कुछ कमी आई, जबकि सेवा क्षेत्र को ऋण में उच्चतर वृद्धि दिखाई दी। भूसंपदा क्षेत्र को ऋण की वृद्धि में कुछ गिरावट के बावजूद यह कई अन्य क्षेत्र की तुलना में उच्चतर बना रहा। मीयादी जमाराशियों में कुछ कमी के बावजूद, बैंकों की जमाराशियों में सुदृढ़ वृद्धि जारी रही। सरकारी प्रतिभूतियों में किए जानेवाले निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई (सारणी 1.1)। तथापि, कुल आस्तियों तथा निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) दोनों के प्रतिशत के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश में गिरावट जारी रही, हालांकि इसकी मात्रा कम थी। निजी क्षेत्र के दो पुराने बैंकों के विलय और एक विदेशी बैंक के अधिग्रहण के साथ बैंकिंग क्षेत्र का समेकन जारी रहा और इस प्रकार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल संख्या मार्च 2007 के अंत के 82 से घटकर मार्च 2008 के अंत में 79 रह गई।

1.31 2007-08 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन को उधार दरों तथा जमा दरों में आई तेजी से समर्थन मिला। कुल आस्तियों के संबंध में बैंकों की निवल ब्याज आय में कुछ गिरावट आई। तथापि, बैंकों की ब्याजेतर आय में वृद्धि हुई, जो आय के स्रोतों को विशाखीकृत करने के उनके प्रयासों को दर्शाता है। परिचालन व्यय (आस्तियों के संबंध में) में कमी आने से बैंक कुल आस्तियों के संबंध में अपने परिचालनगत लाभों को बनाए रख सके। आस्तियों के

प्रतिशत के रूप में बैंकों द्वारा किए गए प्रावधान और आकस्मिकताएं पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी कम थीं। फलस्वरूप अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) में वर्ष के दौरान थोड़ा सुधार हुआ। तथापि, इक्विटी पर उनके प्रतिलाभ (आरओई) में गिरावट आई, जो मुख्यतः पूंजी आधार में वृद्धि के प्रभाव को दर्शाता है क्योंकि बैंकों ने वर्ष के दौरान पूंजी बाजार से संसाधन जुटाए तथा आरक्षित निधि एवं अधिशेष बढ़ाए।

1.32 2007-08 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता में और सुधार हुआ, जो ऋणों और अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में गिरावट में दिखाई दिया। निवल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए पिछले वर्ष के स्तर पर अपरिवर्तित बना रहा। तथापि, 2007-08 में सकल और निवल एनपीए में कुल रूप में वृद्धि हुई क्योंकि एनपीए का नया उपचय वर्ष के दौरान वसूले गए और बढ़ा खाते डाले गए एनपीए से अधिक था। निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों को छोड़कर सभी बैंक समूहों में यह प्रवृत्ति देखी गई।

1.33 पूंजी जुटाने का बैंकों का प्रयास आस्ति वृद्धि तथा नई आस्तियों के जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप रहा। अतः अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात, जो हानियां अवशोषित करने के लिए बैंकिंग प्रणाली की क्षमता का एक उपाय है, एक साल पहले के 12.3 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2008 के अंत में 13.0 प्रतिशत हो गया।

सहकारी बैंक

1.34 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के परिचालनों में 2007-08 के दौरान प्रभावी वृद्धि देखी गई। जमाराशियों में हुई वृद्धि ऋणों और अग्रिमों में हुई वृद्धि से अधिक थी। तथापि, यूसीबी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार लक्ष्य और कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित उपलक्ष्य दोनों में चूक गए। वर्ष के दौरान एसएलआर निवेशों तथा गैर-एसएलआर निवेशों दोनों में वृद्धि के कारण यूसीबी द्वारा निवेश बढ़ गया। परिचालनगत लाभ के रूप में सभी यूसीबी के वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार आया। तथापि, 'प्रावधान, आकस्मिकताएं तथा कर' के अधिक होने के कारण निवल लाभ में कमी आई। यूसीबी की आस्ति

सारणी I.1: वित्तीय क्षेत्र के चुनिंदा संकेतक : 2007-08

श्रेणी	संकेतक	2006-07	2007-08
1	2	3	4
1. अनुसूचित वाणिज्य बैंक	क) प्रमुख समुच्चयों में वृद्धि (प्रतिशत) सकल जमाराशियां ऋण और अग्रिम सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	24.6	23.1
		30.6	25.0
		9.3	22.7
	ख) वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) परिचालनगत लाभ निवल लाभ स्प्रेड	1.9	1.9
		0.9	1.0
		2.6	2.4
	ग) अनर्जक आस्तियां (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में) सकल अनर्जक आस्तियां निवल अनर्जक आस्तियां	2.5	2.3
1.0		1.0	
2. शहरी सहकारी बैंक	क) प्रमुख समुच्चयों में वृद्धि (प्रतिशत) जमाराशियां ऋण	6.4	14.1
		11.3	11.6
	ख) वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) @ परिचालनगत लाभ निवल लाभ स्प्रेड	1.5	1.4
		0.7	0.6
		2.8	2.6
	ग) अनर्जक आस्तियां (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में) सकल अनर्जक आस्तियां निवल अनर्जक आस्तियां	18.3	16.4
		7.8	7.5
3. ग्रामीण सहकारी बैंक	क) संख्या	98,343	-
	ख) प्रमुख समुच्चयों में वृद्धि (प्रतिशत) जमाराशियां ऋण	9.1	-
		11.7	-
	ग) वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) @ लाभ अर्जक सोसाइटियां (संख्या) घाटे में चल रही सोसाइटियां (संख्या) कुल लाभ / हानि (करोड़ रुपए)	34,641	-
		48,529	-
घ) अनर्जक आस्तियां (बकाया अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में)*	-1,405	-	
	19.8	-	
4. वित्तीय संस्थाएं	क) प्रमुख समुच्चयों में वृद्धि (प्रतिशत) ¹ मंजूरी सवितरण	12.9	86.2
		82.8	14.6
	ख) वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) ² परिचालनगत लाभ निवल लाभ स्प्रेड	1.5	1.6
		1.0	1.0
		1.5	1.5
5. जमा लेनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-डी)	क) प्रमुख समुच्चयों में वृद्धि (प्रतिशत) जनता की जमाराशियां	-15.1	-1.9
	ख) वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) निवल लाभ	1.0	2.9
	ग) अनर्जक आस्तियां (निवल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में) ³ निवल अनर्जक आस्तियां	0.2	-8.7
6. अवशिष्ट गैर- बैंकिंग कंपनियां (आरएनबीसी)	क) प्रमुख समुच्चयों में वृद्धि (प्रतिशत) जमाराशियां	12.1	-1.2
	ख) वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) निवल लाभ	0.9	1.5

- : उपलब्ध नहीं

@ : अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित है।

* : प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की बकाया राशियां शामिल हैं।

1. 2006-07 के आंकड़े आइएफसीआइ,सिडबी, ,आइआइबीआइ, आइवीसीएफ,टीएफसीआइ, एलआइसी और जीआइसी तथा उनकी सहायक संस्थाओं से संबंधित है।

2007-08 के आंकड़े सिडबी, आइआइबीआइ, आइवीसीएफ, एलआइसी, जीआइसी तथा उनकी सहायक संस्थाओं से संबंधित है।

2. चार वित्तीय संस्थाओं नामतः एक्जिम् बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी से संबंधित है।

3. रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली कंपनियों के लिए व्यापित में घटबढ़ के साथ।

गुणवत्ता में उल्लेखनीय गिरावट आई क्योंकि सकल और निवल दोनों अनर्जक आस्तियों में कुल रूप से वृद्धि हुई। तथापि, सकल

अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल और निवल दोनों अनर्जक आस्तियों में गिरावट आई।

1.35 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडीबी) को छोड़कर ग्रामीण सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के सभी खंडों के तुलनपत्रों में 2006-07 के दौरान विस्तार हुआ। ग्रामीण सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न खंडों के वित्तीय कार्य-निष्पादन में काफी अंतर देखा गया। जहां अल्पावधि और दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं दोनों के ऊपरी टियर ने 2006-07 में लाभ कमाया, वहीं निम्नतर टियर (अर्थात् प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पीएसीएस) तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी)) ने समग्र हानि उठायी। बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियों के रूप में आस्ति की गुणवत्ता में पीसीएआरडीबी, जिसके लिए यह पिछले साल के स्तर पर रही, को छोड़कर ग्रामीण सहकारी बैंकों की सभी श्रेणियों में सुधार आया। जहां जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी), पीएसीएस तथा पीसीएआरडीबी के वसूली कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ, वहीं राज्य सहकारी बैंकों और एससीएआरडीबी का कार्य-निष्पादन वर्ष के दौरान खराब रहा।

वित्तीय संस्थाएं

1.36 वित्तीय संस्थाओं (एफआइ) द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष के दौरान हुई गिरावट की तुलना में 2007-08 में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। तथापि, संवितरणों में वर्ष के दौरान गिरावट आई। वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत तथा संवितरित वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष हुई क्रमशः 12.9 प्रतिशत और 82.8 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2007-08 में क्रमशः 86.2 प्रतिशत तथा 14.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्वीकृतियों में तीव्र वृद्धि तथा संवितरणों में कमी का हिसाब मुख्यतः निवेश संस्थाओं (विशेषतः एलआइसी) द्वारा लगाया गया।

1.37 2007-08 में वित्तीय संस्थाओं की निवल ब्याज आय में 19.7 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय संस्थाओं की ब्याजेतर आय में भी वर्ष के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तथापि, पिछले साल हुई गिरावट के विपरीत इस वर्ष वित्तीय संस्थाओं के परिचालनात्मक व्यय में 46.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, हालांकि मजदूरी बिल में 32.7 प्रतिशत की उल्लेखनीय गिरावट आई। फलस्वरूप, वर्ष के दौरान परिचालनगत लाभ में 30.1 प्रतिशत

की वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय संस्थाओं के निवल लाभ में भी कर प्रावधान में वृद्धि के बावजूद वृद्धि हुई। वित्तीय संस्थाओं का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9 प्रतिशत के निर्धारित मानदंड की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक बना रहा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

1.38 जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-डी) की कुल आस्तियों/देयताओं में 2006-07 के 28.4 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में 44.8 प्रतिशत की अधिक उच्चतर दर से वृद्धि हुई। उधार, जो एनबीएफसी-डी के लिए निधियों का प्रमुख स्रोत है, में पिछले साल की 30.1 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2007-08 में 55.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जहां निवल स्वाधिकृत निधियों (पूंजी और आरक्षित निधियों) में काफी वृद्धि दर्ज की गई, वहीं जनता की जमाराशियों में 2007-08 में 1.9 प्रतिशत की सीमांत गिरावट आई।

1.39 एनबीएफसी-एनडी-एसआइ की कुल आस्तियों/देयताओं में 2006-07 में हुई 26.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2007-08 में 28.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। एनबीएफसी-एनडी-एसआइ द्वारा अर्जित लाभ में पिछले वर्ष दर्ज की गई 73.4 प्रतिशत की वृद्धि के ऊपर 16.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। एनबीएफसी-एनडी-एसआइ का कुल आस्तियों के प्रति सकल अनर्जक आस्ति अनुपात मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए 2.3 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा। 2006 में एनबीएफसी का एक नया वर्गीकरण अर्थात् आस्ति वित्त कंपनी (एएफसी) प्रभावी हुआ। उत्पादक/आर्थिक कार्यकलापों के लिए वास्तविक/भौतिक आस्तियों का वित्तपोषण करनेवाली कंपनियों को एएफसी के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। मार्च 2008 के अंत में, एनबीएफसी-डी की आस्तियों/देयताओं का सबसे बड़ा हिस्सा (64.1 प्रतिशत आस्ति वित्त कंपनियों के पास था, जो अंशतः एनबीएफसी के पुनर्वर्गीकरण को दर्शाता है।

व्यष्टि वित्त

1.40 हाल के वर्षों में भारत में व्यष्टि वित्त आंदोलन को गति मिल रही है। वर्तमान में भारत में व्यष्टि वित्त की सुपुर्दगी के लिए

दो प्रमुख मॉडल हैं। इनके नाम हैं : एसएचजी-बैंक संपर्क कार्यक्रम (एसबीएलपी) मॉडल तथा व्यष्टि वित्त संस्था (एमएफआइ) मॉडल। एसबीएलपी मॉडल की शुरुआत पहली बार 1992 में नाबार्ड द्वारा प्रायोगिक परियोजना के रूप में की गई, जो अब उधारकर्ताओं की संख्या तथा बकाया ऋण के रूप में एक प्रमुख मॉडल के रूप में उभरा है। व्याप्त के तौर पर, यह मॉडल विश्व का सबसे बड़ा व्यष्टि वित्त कार्यक्रम माना जाता है। गरीबों की आय तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव डालने में व्यष्टि वित्त की संभाव्यता को पहचानते हुए, रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा सिडबी ने कुछ वर्षों से भारत में व्यष्टि वित्त आंदोलन को और गति देने के लिए कई पहल किए हैं। इन नीतिगत गतिविधियों की पृष्ठभूमि में इस आंदोलन द्वारा की गई प्रगति का लेखाजोखा करने के लिए, 'व्यष्टि वित्त' नामक एक नया अध्याय इस रिपोर्ट में शुरू किया गया है।

1.41 एसबीएलपी ने 1990 के दशक के प्रारंभ में हुई इसकी शुरुआत से बैंकों के साथ जुड़े एसएचजी ऋण के सदस्य तथा एसएचजी द्वारा संवितरित बैंक ऋण दोनों के रूप में काफी प्रगति की है। 31 मार्च 2007 को (अब तक का नवीनतम उपलब्ध आंकड़ा) 2.9 मिलियन एसएचजी के पास एसबीएलपी कार्यक्रम के तहत 12,366 करोड़ रुपए का बकाया बैंक ऋण था। 31 मार्च 2007 को बैंकिंग क्षेत्र के पास बचत बैंक खाता रखनेवाले एसएचजी की संख्या 4.2 मिलियन तथा बकाया बचत राशियां 3,513 करोड़ रुपए थीं, जिसके द्वारा इस कार्यक्रम के तहत 58 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों को कवर किया गया था।

1.42 गरीबों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में संलग्न बैंकों से इतर संस्था के रूप में एमएफआइ की उभरती भूमिका की पहचान की जा रही है और बैंकिंग क्षेत्र आगे एसएचजी को ऋण देने के लिए एमएफआइ को ऋण दे रहा है। वर्ष 2006-07 (अब तक का नवीनतम उपलब्ध आंकड़ा) के दौरान, 1,152 करोड़ रुपए का बैंक ऋण 334 एमएफआइ को वितरित किया गया और इस प्रकार कुल बकाया ऋण 31 मार्च 2007 को 1,584 करोड़ रुपए हो गया, जो 550 एमएफआइ को दिया गया था।

2008-09 की गतिविधियां

1.43 केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) द्वारा 28 नवंबर 2008 को जारी 2008-09 की दूसरी तिमाही के अनुमान के अनुसार, पिछले साल की तदनु रूप तिमाही के 9.3 प्रतिशत की तुलना में जुलाई-सितंबर 2008 के दौरान जीडीपी में वास्तविक वृद्धि का अनुमान 7.6 प्रतिशत लगाया गया था। तीनों क्षेत्रों अर्थात् कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप, उद्योग और सेवा में मंदी फैल गई थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2008 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) 2007 के उसी माह की तुलना में गिरकर 4.8 प्रतिशत रह गया। अप्रैल-सितंबर 2008 में संचयी वृद्धि अप्रैल-सितंबर 2007 के 9.5 प्रतिशत की तुलना में कम होकर 4.9 प्रतिशत रह गई।

1.44 साल-दर-साल आधार पर थोक मूल्य सूचकांक में घटबढ़ द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति 2 अगस्त 2008 को बढ़कर 12.9 प्रतिशत की अंतर्वर्ष ऊंचाई पर पहुंच गई, जबकि मार्च 2008 के अंत में यह 7.7 प्रतिशत थी। बाद में, डब्ल्यूपीआइ वार्षिक मुद्रास्फीति 22 नवंबर 2008 को कम होकर 8.4 प्रतिशत रह गई जो मुक्त रूप से मूल्य-निर्धारित पेट्रोलियम उत्पादों, तिलहनों/खाद्य तेलों/खली, कच्ची रूई, सूती वस्त्र तथा लोहा और इस्पात के मूल्यों में गिरावट द्वारा चालित थी। प्राथमिक वस्तुओं एवं विनिर्मित उत्पादों की वार्षिक मुद्रास्फीति दरें मार्च 2008 के अंत के स्तरों (क्रमशः 9.7 प्रतिशत तथा 7.3 प्रतिशत) की तुलना में उच्चतर (22 नवंबर 2008 को क्रमशः 12.0 प्रतिशत तथा 8.1 प्रतिशत) थीं, जबकि ईंधन समूह की दरें मार्च 2008 के अंत के स्तर (6.8 प्रतिशत) की तुलना में न्यूनतर (5.3 प्रतिशत) थीं। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के विभिन्न उपायों को जून 2008 के 7.3-8.8 प्रतिशत तथा अक्टूबर 2007 के 5.5-7.0 प्रतिशत की तुलना में सितंबर/अक्टूबर 2008 के दौरान 9.5-11.1 प्रतिशत के दायरे में रखा गया।

1.45 2008-09 के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त के प्रमुख घाटा संकेतकों के बारे में बजट अनुमान लगाया गया है कि वे कुल तथा जीडीपी के अनुपात दोनों रूपों में 2007-08 के संशोधित अनुमानों की तुलना में घट जाएंगे। प्राथमिक शेष में अधिशेष

2008-09 (बजट अनुमान) में बढ़कर जीडीपी का 0.8 प्रतिशत होने का बजट अनुमान है। कर प्राप्ति में उछाल से यह आशा है कि राजस्व प्राप्तियां बढ़ जाएंगी (2008-09 में जीडीपी का 0.4 प्रतिशत), जबकि जीडीपी के अनुपात के रूप में राजस्व व्यय 2007-08 (संशोधित अनुमान) के स्तर पर बना रहा। राजस्व खाते में परिकल्पित सुधार से संयुक्त राजस्व घाटा को जीडीपी का 0.4 प्रतिशत घटने की आशा है। राजस्व खाते में प्रत्याशित सुधार से भी यह आशा है कि वह संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) को 2008-09 में जीडीपी का 0.7 प्रतिशत कम करने में उल्लेखनीय अंशदान करेगा।

1.46 2008-09 की दूसरी तिमाही में मौद्रिक तथा चलनिधि समुच्चयों में कुछ मंदी देखी गई जो अंशतः पूंजी प्रवाहों में गिरावट दर्शाते हैं। राजकोषीय वर्ष 2008-09 में (21 नवंबर 2008 तक) स्थूल मुद्रा (एम₃) में 2008-09 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य की पहली तिमाही की समीक्षा (जुलाई 2008) में निर्धारित 17.0 प्रतिशत की सांकेतिक सीमा के ऊपर साल-दर-साल आधार पर वृद्धि हुई। साल-दर-साल आधार पर एम₃ की वृद्धि एक साल पहले के 23.0 प्रतिशत की तुलना में 21 नवंबर 2008 को 19.0 प्रतिशत थी। वित्तीय वर्ष के आधार पर मुद्रा आपूर्ति (एम₃) में पिछले साल की तदनुरूप अवधि के 11.0 प्रतिशत की तुलना में 21 नवंबर 2008 तक 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.47 वाणिज्यिक क्षेत्र को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण में एक साल पहले के 23.1 प्रतिशत की तुलना में 21 नवंबर 2008 को 27.0 प्रतिशत (साल-दर-साल) की वृद्धि हुई। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा खाद्येतर ऋण में एक साल पहले के 23.7 प्रतिशत की तुलना में 21 नवंबर 2008 को साल-दर-साल 26.9 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि हुई। जमा वृद्धि के विस्तार की तुलना में ऋण वृद्धि के उच्चतर विस्तार के फलस्वरूप अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात (साल-दर-साल) एक साल पहले के 65.9 प्रतिशत की तुलना में 21 नवंबर 2008 को 93.7 प्रतिशत पर उच्चतर था। 28 सितंबर 2008 तक उपलब्ध अलग-अलग क्षेत्रवार आंकड़े यह दर्शाते हैं कि वृद्धिशील खाद्येतर ऋण (साल-दर-साल) का लगभग 48 प्रतिशत उद्योग के लिए तथा 9 प्रतिशत

कृषि के लिए, लगभग 14 प्रतिशत व्यक्तिगत ऋणों के लिए दिया गया, जिसमें से लगभग 38 प्रतिशत आवास ऋणों के लिए दिया गया था। इस अवधि में उद्योग को खाद्येतर ऋण में वृद्धि की अगुवाई मूलभूत संरचना (पॉवर, बंदरगाह और दूरसंचार), पेट्रोलियम, लोहा और इस्पात, वस्त्र, रसायन, इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण और वाहन उद्योगों द्वारा की गई। वाणिज्यिक भू-संपदा को दिए गए ऋण में वृद्धि कुछ मंदी के बावजूद अधिक बनी रही।

1.48 2008-09 के दौरान अब तक चलनिधि की स्थितियों तथा मुद्रा बाजार की दरों में हुई घटबढ़ को मोटे तौर पर दो चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है जो सितंबर 2008 के मध्य से देशी वित्तीय बाजारों पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में हुए विघटनों के प्रभाव द्वारा विभाजित है। पहले चरण (अप्रैल से सितंबर 2008 के मध्य तक) के दौरान, पूंजीगत अंतर्वाहों के बंद होने तथा फलस्वरूप रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा बाजार परिचालनों में मई 2008 तक निवल हाजिर खरीद से उसके बाद (अगस्त 2008 को छोड़कर) निवल हाजिर बिक्री तक आए टर्नअराउंड ने देशी चलनिधि के सृजन को प्रतिबंधित कर दिया। सितंबर 2008 के मध्य से प्रारंभ हुए दूसरे चरण के दौरान, विश्व की कुछ सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं के दिवालियेपन/बिक्री/पुनर्विन्यास द्वारा प्रेरित असाधारण वैश्विक गतिविधियां अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजारों के अत्यधिक विघटन, पूरे विश्व में शेयर बाजारों में तीव्र गिरावट तथा निवेशकों के जोखिम से अत्यधिक बचने के रूप में परिणत हुईं। इन गतिविधियों के कारण सितंबर 2008 के मध्य के दौरान अग्रिम कर बहिर्वाह जैसे अस्थायी स्थानीय कारकों के साथ देशी मुद्रा और विदेशी मुद्रा बाजारों पर दबाव आया। एलएएफ मार्ग के जरिए औसत अंतर्वेश सितंबर 2008 में 43,000 करोड़ रुपए तथा आगे अक्टूबर 2008 में 46,000 करोड़ रुपए हो गया। इस पर्याप्त नरमी के कारण नवंबर 2008 के मध्य से चलनिधि की सुखद स्थिति सुनिश्चित की गयी है, जैसाकि अनेक संकेतकों में दिखाई देता है। 18 नवंबर 2008 से, एलएएफ की सुविधा का उपयोग अधिकांशतः अवशोषण के लिए किया गया है। औसत दैनिक निवल बकाया चलनिधि अंतर्वेश गिरकर नवंबर 2008 के दौरान लगभग 8,017 करोड़ रुपए रह गया।

1.49 सीपी पर डब्ल्यूएडीआर 31 मार्च 2008 के 13.16 प्रतिशत से गिरकर मई 2008 के मध्य तक 8.57 प्रतिशत हो गया परंतु उसके बाद अन्य मुद्रा बाजार दरों के अनुरूप बढ़कर नवंबर 2008 के मध्य तक 12.28 प्रतिशत हो गया। सीपी की सर्वाधिक पसंदीदा परिपक्वता अवधि '181 दिन और अधिक' थी। सीडी पर डब्ल्यूएडीआर मार्च 2008 के अंत के 10.0 प्रतिशत से घटकर जून 2008 के अंत में 9.16 प्रतिशत हो गया परंतु उसके बाद बढ़कर अक्टूबर 2008 तक वह 12.57 प्रतिशत हो गया। अक्टूबर के अंत में, सीडी पर डब्ल्यूएडीआर अन्य मुद्रा बाजार दरों के अनुरूप घटकर 10.0 प्रतिशत हो गया।

1.50 उच्चतर मुद्रास्फीति को देखते हुए और उच्चतर मुद्रा बाजार ब्याज दरों के अनुरूप, खजाना बिलों (टीबी) पर प्राथमिक बाजार प्रतिफल 2008-09 की दूसरी तिमाही में बढ़ गया। 364 दिवसीय तथा 91 दिवसीय खजाना बिलों के बीच प्रतिफल का स्प्रेड नवंबर 2008 में 4 आधार अंक (मार्च 2008 में 7 आधार अंक) था।

1.51 2008-09 (18 नवंबर 2008 तक) में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने विभिन्न परिपक्वताओं के लिए जमा ब्याज दरों में 50-175 आधार अंकों की वृद्धि की। एक साल से तीन साल तक की परिपक्वतावाली जमाराशियों पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा प्रस्तावित ब्याज दरें मार्च 2008 के 8.25-9.25 प्रतिशत से बढ़ाकर नवंबर 2008 में 9.00-10.50 प्रतिशत के दायरे में कर दी गईं। उधार देने के पक्ष में, पीएसबी की बेंचमार्क मूल उधार दरें (बीपीएलआर) मार्च 2008 के 12.25-13.50 प्रतिशत से बढ़कर नवंबर 2008 तक 13.00-14.75 प्रतिशत हो गईं। निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों ने भी उसी अवधि में अपना बीपीएलआर क्रमशः 13.00-16.50 प्रतिशत तथा 10.00-15.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 13.00-17.75 प्रतिशत तथा 10.00-17.00 प्रतिशत कर दिया। तदनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों का भारित औसत बीपीएलआर मार्च 2008 के क्रमशः 12.8 प्रतिशत, 15.1 प्रतिशत और 13.9 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2008 में क्रमशः 13.99 प्रतिशत, 16.42 प्रतिशत और 14.73 प्रतिशत हो गया।

1.52 2008-09 (2 दिसंबर 2008 तक) के दौरान भारतीय रुपए में सामान्यतः मूल्यहास हुआ तथा वह 39.89-50.53 रुपया प्रति अमरीकी डालर के दायरे में रहा। अप्रैल 2008 के आरंभ से रुपए में मूल्यहास हुआ, जो एफआइआइ के बहिर्वाह, शेयर बाजार में मंदड़िया स्थिति, उच्च मुद्रास्फीति एवं कच्चे तेल की उच्चतर कीमतों को दर्शाता है, जिनके कारण डालर की मांग अधिक रही। रुपए की विनिमय दर मार्च 2008 के अंत के 39.99 रु. प्रति डालर की तुलना में 2 दिसंबर 2008 को 50.53 रु. प्रति डालर थी। इस स्तर पर भारतीय रुपए में 31 मार्च 2008 के स्तर की तुलना में 20.9 प्रतिशत का मूल्यहास हुआ। उसी अवधि में रुपए में पौंड-स्टर्लिंग की तुलना में 5.9 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई परंतु यूरो की तुलना में 1.0 प्रतिशत, जापानी येन की तुलना में 26.2 प्रतिशत और चीनी युआन की तुलना में 22.1 प्रतिशत का मूल्यहास हुआ।

1.53 बीएसई सेंसेक्स मार्च 2008 के अंत के स्तर की तुलना में 41.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करते हुए 8 दिसंबर 2008 को 9163 पर बंद हुआ। 2008-09 के दौरान देशी शेयर बाजारों के कार्य-निष्पादन में चार अलग-अलग चरण देखे गए। 1 अप्रैल और 21 मई 2008 के बीच के पहले चरण में बाजार में सुधार हुआ। 22 मई और 16 जुलाई 2008 के दूसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, देशी खुदरा ईंधन की कीमतों में वृद्धि, देशी मुद्रास्फीति दर में वृद्धि, भारतीय इक्विटी बाजार में एफआइआइ द्वारा निवल बिक्री, बढ़ते व्यापार घाटे और रुपए में मूल्यहास पर चिंता, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय इक्विटी बाजारों में गिरावट के रुख, देशी राजनैतिक अनिश्चितता तथा अन्य क्षेत्र और स्टाक-विशिष्ट समाचारों के कारण बाजार के रुख में सतर्कता आ गई। 17 जुलाई 2008 से सितंबर 2008 के पहले सप्ताह तक के तीसरे चरण में देशी शेयर बाजारों में कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के कारण बीच-बीच में हुए कुछ करेक्शन के बावजूद सुधार हुआ। सितंबर 2008 के दूसरे सप्ताह से प्रारंभ हुए चौथे चरण में देशी शेयर बाजार विश्व की कुछ सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं के दिवालियेपन/बिक्री/पुनर्विन्यास के कारण अस्थिर और कमजोर हो गए जिसके फलस्वरूप अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों

में अत्यंत विघटन, एफआइआइ द्वारा भारी निवल बिक्री, वैश्विक धातु मूल्यों में गिरावट, औद्योगिक एवं निर्यात वृद्धि में मंदी, अप्रत्यक्ष कर वसूलियों में गिरावट तथा कंपनियों की आय वृद्धि में गिरावट की स्थिति आई।

1.54 भारत का पण्य निर्यात, जो अगस्त 2008 तक लचीला बना रहा (अप्रैल-अगस्त 2008 के दौरान 35.3 प्रतिशत), सितंबर 2008 में गिर गया (10.4 प्रतिशत) तथा अक्टूबर 2008 में निर्यात में ऋणात्मक वृद्धि (-12.1 प्रतिशत) दर्ज की गई। डीजीसीआइएण्डएस द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-अक्टूबर 2008 के दौरान भारत के पण्य निर्यात और आयात में क्रमशः 23.3 प्रतिशत और 36.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो एक साल पहले दर्ज की गई क्रमशः 22.7 प्रतिशत और 27.4 प्रतिशत की वृद्धि से उच्चतर थी। अप्रैल-अक्टूबर 2008 में तेल आयात में बनी हुई वृद्धि के कारण पण्य व्यापार घाटा बढ़ गया।

2008-09 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति में चालू खाता घाटा बढ़कर 10.7 बिलियन अमरीकी डालर होना तथा पूंजीगत प्रवाहों में गिरावट दिखाई दी। अदृश्य मदों के तहत सॉफ्टवेयर निर्यात और निजी अंतरणों में वृद्धि की अगुवाई में निवल अधिशेष में उछाल बना रहा। पण्य व्यापार घाटे में बड़ी वृद्धि के कारण चालू खाता घाटा में अप्रैल-जून 2007 के स्तर की तुलना में वृद्धि हुई। 2008-09 में अब तक निवल पूंजी अंतर्वाह अस्थिर बना रहा। जहां अप्रैल-सितंबर 2008 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ गया, वहीं संविभाग निवेश में अप्रैल-अक्टूबर 2008 के दौरान बहिर्वाह दिखाई दिया। 2008-09 (28 नवंबर 2008 तक) में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में मार्च 2008 के अंत के स्तर की तुलना में 62.0 बिलियन अमरीकी डालर की गिरावट आई और वह 28 नवंबर 2008 को 247.7 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।